आकाशवाणी
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 18.02.2026 समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- गुजरात में आयोजित सहकारिता मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और मिलेट मिशन की सराहना की गई।
- आवास विभाग, प्रदेश के बड़े शहरों और पयर्टन केंद्रों पर जाम की समस्या दूर करने के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत। राज्य के 11 स्थानों पर जल्द ही पार्किंग सुविधा मिलेगी।
- ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। महिला स्वयं सहायता समूहों के आजीविका संवर्धन पर जोर दिया।
- पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विशेष टीबी मुक्त अभियान चलाया जाएगा।

सहकारिता मंत्री

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुजरात में आयोजित सहकारिता मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, मिलेट्स मिशन और दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की सराहना की गई। साथ ही इन योजनाओं को मॉडल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाये जाने पर भी विचार किया गया, ताकि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत किसानों की आय में वृद्धि, पशुधन अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण आजीविका सहित पोषण योजनाओं को प्रोत्साहन मिल सके। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में राज्य सरकार की ओर से सहकारिता के क्षेत्र में संचालित विभिन्न नवाचारी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया गया। इनमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना तथा मिलेट्स मिशन योजना शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य में इन परिवर्तनकारी योजनाओं को लागू किया गया है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण विकास, आर्थिक सशक्तिकरण व सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है। साथ ही किसानों की आय में वृद्धि, पशुधन अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण आजीविका, मिलेट उत्पादन व पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना है। डॉ. रावत ने बैठक में रूद्रप्रयाग, बागेश्वर ओर चम्पावत जिलों में जिला सहकारी बैंकों के संचालन को लेकर लाइसेंस प्रदान किए जाने की मांग भी रखी।

पार्किंग स्थल

आवास विभाग, प्रदेश के बड़े शहरों, तीर्थ स्थलों और पयर्टन केंद्रों पर जाम की समस्या दूर करने के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में राज्य के 11 स्थानों पर जल्द ही पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें एक हजार 82 वाहन पार्क हो सकेंगे। पहले चरण में प्रदेश के 54 स्थानों पर कुल 3 हजार 244 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब दूसरे चरण में 11 अन्य स्थानों पर पार्किंग निर्माण करीब 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। आवास विभाग ने इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा विभिन्न विकास प्राधिकरणों की ओर से भी अपने संसाधनों से 11 अन्य स्थानों पर पार्किंग निर्माण किया जा रहा है, जिससे 359 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सचिव, आवास, डॉ आर. राजेश कुमार ने सभी विकास प्राधिकरणों को पार्किंग निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी यात्रा सीजन से पहले सभी चिन्हित स्थानों पर पार्किंग सुविधा बहाल की जाए। साथ ही पार्किंग स्थलों पर शौचालय, लाइट और साफ सफाई की भी उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं।

वनाग्नि मॉक ड्रिल

प्रदेश में आज सभी वन प्रभाग, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्यों में वनाग्नि को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें वन विभाग के अलावा आपदा प्रबन्धन विभाग, राजस्व, पुलिस संचार, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य आदि विभाग भाग लेंगे। इसके अलावा वन पंचायत, ग्राम स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समितियां, महिला व युवा मंगल दल, स्वंय सेवी संस्था भी इसमें शामिल होंगे। मॉक ड्रिल का उद्देश्य वनाग्नि नियंत्रण के दौरान विभिन्न विभागों के आपसी तालमेल और तैयारियों को परखना है।

गणेश जोशी

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने योजनाओं के प्रभावी व समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। ग्राम्य विकास मंत्री ने विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों के आजीविका संवर्धन पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सामुदायिक संस्थाओं को उद्यम विकास की दिशा में प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन को आपस में जोड़कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। श्री जोशी ने अधिकारियों को महिला आय–सृजन कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाने तथा केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित समय–सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 57 हजार स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जा चुका है और राज्य में 2 लाख 53 हजार महिलाएं "लखपति दीदी" बन चुकी हैं।

टीबी मुक्त अभियान

पौड़ी जिले में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इस महीने के अंतिम सप्ताह की शुरुआत से 100 दिन का विशेष टीबी मुक्त अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित अभियान के तहत उन लोगों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिन्हें संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है। विभाग की टीमें गांव–गांव जाकर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीजों के साथ ही धूम्रपान करने वाले लोगों की नॉट टेस्ट व एक्स–रे के द्वारा विशेष जांच करेंगी। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बीमार लोगों की पहचान के लिए आशा कार्यकत्रियां और एएनएम घर–घर जाकर सर्वे करेंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला ने बताया कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में एक हजार 166 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 609 ग्राम पंचायतें, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दौरान लोगों में टी.बी. के लक्षण, समय पर जांच, नियमित उपचार और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाए जाने को लेकर जोर दिया जाएगा।

जन–जन की सरकार

'जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार अभियान के तहत देहरादून जिले में चकराता विकासखंड के लाखामंडल में संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉ. हर्षिता सिंह की अध्यक्षता में जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही विभिन्न विभागीय योजनाओं के माध्यम से एक हजार 844 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही, शिविरों में आवश्यक प्रमाण पत्र भी मौके पर ही जारी किए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों को तहसील और जिला मुख्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार की ख़बर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। अमर उजाला प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है– दुनिया की तीन ए.आई महाशक्तियों में शामिल होगा भारत। कहा– ए.आई को अवसर के रूप मूं महसूस करेंगे भारतीय, रोजगार पर खतरे के रूप में नहीं।

राज्य सरकार नौ से तेरह मार्च तक गैससैंण में बजट सत्र का आयोजन करेगी। हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार विधानसभा सत्र के लिये विधायकों के अभी तक करीब पांच सौ दस सवाल आ चुके हैं। इसी ख़बर पर मुख्यमंत्री के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है– सभी वर्गों के हितधारकों के सुझाव बजट में शामिल होंगे।

उत्तराखंड के 131 गांव और तीन शहरों में पहले होगी जनगणना। हिंदुस्तान समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ ख़बर लिखता है कि इन गांव व शहरों में सितंबर में जनगणना कराई जाएगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में जनगणना अगले साल नौ से 28 फरवरी के बीच कराई जाएगी।

अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक, देहरादून में हुए घोटाले के बाद आर.बी.आई की ओर से बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए है। दैनिक जागरण के अनुसार बैंक में ग्राहकों के एक सौ चौबीस करोड़ रुपए फंसे हैं। समाचार पत्र के अनुसार बैंक घाटे में था, फिर भी वह अपने को फायदे में दिखा रहा था।

445 प्रजातियों सहित दूसरा समृद्ध पक्षी राज्य उत्तराखंड। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है– बर्ड काउंट इंडिया द्वारा तेरह से सोलह फरवरी तक आयोजित इस अभियान मे देशभर से एक हजार चौवन पक्षी प्रजातियां दर्ज की गईं।